खास-खबरें

इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक अथॉरिटी का गठन देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा : खंडेलवाल

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (आईटीएलए) एसपीवी के गठन को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे विकसित भारत, गति शक्ति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विजन को मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

उन्होंने कहा कि इससे देश के व्यापार एवं उद्योग को भी बड़ा लाभ होगा। भारत की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, सप्लाई चेन को अधिक सक्षम बनाने तथा परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैट महामंत्री ने कहा कि वर्तमान में देश में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई परिवहन तथा वेयरहाउसिंग से जुड़े विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, इसलिए आईटीएलए का गठन इस दिशा में एक प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था प्रदान करेगा।

ओप्पो ने लॉन्च किए एफ 35 प्रो 5जी और एफ 35 5जी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत में ओप्पो की एफ सीरीज के 10 वर्ष पूरे होने के मौके पर कंपनी ने एफ 35 सीरीज लॉन्च की है। इसमें ओप्पो एफ 35 प्रो 5जी और ओप्पो एफ 35 5जी शामिल हैं। कंपनी के अनुसार एफ सीरीज ने पहली पीढ़ी के एफ1 के साथ 'सेल्फी एक्सपर्ट' के तौर पर शुरुआत की थी और अब एफ 35 सीरीज के साथ 'ग्रुप सेल्फी एक्सपर्ट' के रूप में आगे बढ़ रही है। ओप्पो इंडिया के प्रमुख-संचार गोल्डी पटनायक ने बताया कि नई सीरीज में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड नेचुरल सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसका 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है। इससे एक फ्रेम में अधिक लोगों और पलों को शामिल किया जा सकेगा। कंपनी के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में एफ सीरीज के 3 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन बिक चुके हैं। ओप्पो एफ 35 प्रो 5जी के 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 45,999 रुपए, 8 जीबी रैम और 128 जीबी मॉडल की कीमत 49,999 रुपये तथा 8 जीबी रैम और 256 जीबी मॉडल की कीमत 54,999 रुपये रखी गई है।

विमान ईंधन की ऊंची कीमतों को लेकर एयरलाइन, तेल कंपनियों से बातचीत जारी: नागरिक उड्डयन मंत्री

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण विमान ईंधन की ऊंची कीमतों को लेकर मंत्रालय एयरलाइन तथा तेल कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन ने राजधानी नई दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट (आईक्यूएफएम) सम्मेलन से इतर यह बात कही। नायडू ने बताया कि एक जॉइंट वेंचर के जरिए भारत को दो साल के भीतर अपना पहला स्वदेशी सिविलियन एयरक्राफ्ट मिल जाएगा।

नायडू ने कहा, ''सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह है कि पश्चिम एशिया संकट एटीएफ की कीमतों पर कितना बोझ डाल रहा है। हम विमानन कंपनियों और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के साथ बातचीत कर रहे हैं।''

छोटे व मध्यम उद्यमों को 10 हजार करोड़ रुपए का विकास कोष

केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला, विनिर्माण, सेवा, प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित उद्यमों को मिलेगा विकास पूंजी का समर्थन

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य विकास के चरण में पहुंच चुके उद्यमों को इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराना और विनिर्माण, सेवा, प्रौद्योगिकी, नवाचार आधारित क्षेत्रों तथा रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं में भारतीय कंपनियों के विस्तार को बढ़ावा देना है।

यह पहल केंद्रीय बजट 2026-27 में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए इक्विटी, नकदी उपलब्धता और पेशेवर सहायता बढ़ाने से जुड़ी घोषणाओं के अनुरूप है। सरकार के अनुसार, मौजूदा इक्विटी सहायता योजनाओं का बड़ा हिस्सा शुरुआती चरण के उद्यमों और सूक्ष्म इकाइयों पर केंद्रित है। ऐसे में लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विकास पूंजी की कमी को दूर करना जरूरी है।

एसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, निर्यात, विनिर्माण उत्पादन और नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऋण तक पहुंच बेहतर होने के बावजूद विस्तार, नई तकनीक अपनाने, अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश, अधिग्रहण और बड़े स्तर पर कारोबार बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक जोखिम पूंजी की कमी बनी हुई है। एसएमई ग्रोथ फंड इसी कमी को दूर करने के लिए उच्च क्षमता वाले उद्यमों को विकास इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगा।

फंड से मिलने वाली अधिकांश राशि लघु एवं मध्यम विनिर्माण केंद्रित उद्यमों को आवंटित की जाएगी। इसके दायरे में टियर-2 और टियर-3 शहरों के औद्योगिक समूहों में काम करने वाले एसएमई भी शामिल होंगे। सरकार के अनुसार, दीर्घकालिक पूंजी मिलने से कंपनियां परिचालन क्षमता बढ़ाने, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षमता में निवेश करने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने में सक्षम होंगी। इस पहल के तहत सरकार औद्योगिक विकास कोष ढांचे के अंतर्गत स्थापित वैकल्पिक निवेश कोष में कुल 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। विनिर्माण उद्यमों को क्षमता विस्तार और उन्नत तकनीक अपनाने में सहायता मिलने से उत्पादकता और निर्यात प्रतिस्पर्धा मजबूत होने की उम्मीद है।

औद्योगिक समूहों में निवेश से स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती मिलेगी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार के अनुसार, यह कोष उच्च विकास क्षमता वाले उद्यमों, नवाचार आधारित औद्योगीकरण और प्रतिस्पर्धी भारतीय कंपनियों की नई पीढ़ी को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त के साथ बंद

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार तेजी रही। सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 220 अंक की बढ़त दर्ज की गई और यह 22,776 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में फार्मा, एफएमसीजी और निजी बैंकों के शेयरों में अधिक खरीदारी देखने को मिली।

आज दो कंपनियों शाह इन्वेस्टर्स होम लिमिटेड और एसआरआईटी इंडिया के शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुए। दोनों कंपनियों के शेयरों की सकारात्मक शुरुआत हुई। शाह इन्वेस्टर्स होम लिमिटेड के शेयर एनएसई और बीएसई पर 171 रुपये पर सूचीबद्ध हुए, जबकि इसका निर्गम मूल्य 167 रुपये था। दोनों एक्सचेंजों पर शेयर 2.40 प्रतिशत प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध हुआ। एसआरआईटी इंडिया के शेयर एनएसई पर 144.90 रुपये और बीएसई पर 139.80 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। इसका निर्गम मूल्य 130 रुपये था।

एनएसई पर शेयर 11.46 प्रतिशत और बीएसई पर 7.54 प्रतिशत प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध हुआ। एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.89 प्रतिशत गिरा, जबकि जापान का निक्केई 1.05 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग 1 प्रतिशत बढ़ा। विदेशी निवेशकों ने पिछले सात दिनों में 24,332 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इसी अवधि में 26,495 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की। इससे पहले 5 अक्टूबर को सेंसेक्स 473 अंक बढ़कर 72,382 और निफ्टी 134 अंक की बढ़त के साथ 22,556 पर बंद हुआ था।

भारत-स्विट्ज़रलैंड विज्ञान साझेदारी होगी मजबूत, अनुसंधान के लिए 4.5 करोड़ स्विस फ्रैंक का प्रावधान

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के दीर्घकालिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक में संस्थागत भागीदारी और उभरते क्षेत्रों में संयुक्त कार्य को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, टीका विकास, जीनोम अनुक्रमण, अंतरिक्ष और गहरे समुद्र अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मिशन आधारित दृष्टिकोण अपना रहा है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं।

उन्होंने भारत-स्विट्जरलैंड अनुसंधान ढांचे और संयुक्त वैज्ञानिक बोर्ड की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया। स्विस राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच आशय पत्र तथा ज्यूरिख एप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौते को भी महत्वपूर्ण कदम बताया गया। राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन ने कहा कि स्विट्जरलैंड भारत को तेजी से उभरती वैश्विक अनुसंधान एवं विकास शक्ति मानता है और शिक्षा, अनुसंधान तथा नवाचार के क्षेत्र में उसे दीर्घकालिक भागीदार बनाना चाहता है। उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ अनुसंधान साझेदारी के लिए 45 मिलियन स्विस फ्रैंक निर्धारित किए हैं और भारत से भी समान प्रतिबद्धता की अपेक्षा है। दोनों पक्षों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उसके व्यापक उपयोग पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति पार्मेलिन ने विकासशील देशों को एआई से लाभ पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया और भारत को आगामी जिनेवा एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग वर्ष 2003 में हुए अंतर-सरकारी समझौते के बाद से लगातार बढ़ा है। यह साझेदारी क्वांटम तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, महासागर अनुसंधान, उन्नत सामग्री, औषधि, जैव चिकित्सा अनुसंधान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक विस्तारित हो चुकी है।

परिवहन और लॉजिस्टिक्स की एकीकृत योजना के लिए बनेगा नया प्राधिकरण

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में समन्वय बढ़ाने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण यानी आईटीएलए की स्थापना को मंजूरी दी है। इसे विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य परिवहन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और उनके क्रियान्वयन में मौजूद समन्वय की कमी को दूर करना है।

आईटीएलए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना, अनुसंधान, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी, नीतिगत सहयोग और आंकड़ा विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। यह दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसमें सड़क, रेलवे,

बंदरगाह और जहाजरानी, नागरिक विमानन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय जहाजरानी, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को शामिल किया जाएगा।

प्राधिकरण परिवहन मंत्रालयों की करीब पांच वर्ष की क्षेत्रीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं का भी मूल्यांकन करेगा, ताकि वे राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान के अनुरूप रहें और बहु-माध्यम परिवहन ढांचे का विकास हो सके।

आईटीएलए केंद्र सरकार की 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा। इन परियोजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन मौजूदा व्यवस्था के तहत ही जारी रहेगा। प्राधिकरण 500 करोड़ रुपये से अधिक की परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करेगा तथा उनके क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। परियोजनाएं पूरी होने के बाद उनके प्रभाव का आकलन भी किया जाएगा।

प्राधिकरण राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार भी तैयार करेगा। इसके लिए जीएसटी नेटवर्क, ई-वे बिल, फास्टैग, वाहन, जीपीएस आधारित प्रणालियों और शहरी यातायात प्रबंधन प्रणालियों सहित विभिन्न स्रोतों से आंकड़े जुटाए जाएंगे। इनका उपयोग परिवहन योजना, निगरानी और प्रभाव आकलन में किया जाएगा।

आईटीएलए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 की समीक्षा और अद्यतन में सहायता करेगा। साथ ही लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रशिक्षण, कौशल विकास, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे बुनियादी ढांचे की दक्षता बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और भारत की वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

आधार में पूरा नाम बदलने के लिए अब गजट अधिसूचना जरूरी

मामूली वर्तनी सुधार के लिए पहचान पत्र पर्याप्त, बड़े बदलाव के लिए गजट अधिसूचना देना होगा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: आधार कार्ड में नाम की वर्तनी सुधारने, सरनेम बदलने या पूरा नाम बदलने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने नए नियम लागू किए हैं। अब नाम में किए जाने वाले अलग-अलग बदलावों के लिए अलग दस्तावेज जमा करने होंगे। धोखाधड़ी रोकने के लिए जमा किए गए दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी।

नाम में मामूली बदलाव को लघु नाम परिवर्तन माना जाएगा। इसमें वर्तनी की छोटी गलती सुधारना, मध्य या अंतिम नाम जोड़ना अथवा हटाना और नाम का क्रम बदलना शामिल है। इसके लिए एक मान्य पहचान पत्र

देना होगा। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले में परिवार के मुखिया के आधार पर संबंध प्रमाण भी मान्य रहेगा।

यदि सही दस्तावेज देने के बावजूद आधार में नाम गलत दर्ज हो गया है और गलती आंकड़ा प्रविष्टि के दौरान हुई है, तो वयस्कों के लिए परिशिष्ट बी और बच्चों के लिए परिशिष्ट सी के साथ पहचान या संबंध का प्रमाण देना होगा। नया नाम पहले जमा किए गए दस्तावेजों से मेल खाना जरूरी होगा।

शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलने के लिए पहचान पत्र के साथ परिशिष्ट डी का शपथपत्र देना होगा। इसमें स्पष्ट करना होगा कि नाम परिवर्तन शादी या तलाक के कारण किया जा रहा है। इसके विकल्प के रूप में पंजीकृत विवाह प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जाएगा। लिंग परिवर्तन के बाद नाम बदलने के लिए भी पहचान पत्र देना होगा।

कुछ बदलाव बिना दस्तावेज के किए जा सकेंगे। नाम में बड़े और छोटे अक्षरों की गलती ठीक करने या नाम से बिंदु हटाने के लिए दस्तावेज जरूरी नहीं होगा। उपनाम या वैकल्पिक नाम में से किसी एक को चुनने के लिए वयस्कों को परिशिष्ट ई और बच्चों को परिशिष्ट एफ का शपथपत्र देना होगा। आधार में सैन्य रैंक या पद जोड़ने की अनुमति नहीं है।

वस्त्र उद्योग के विकास के लिए पहली बार डीसीटीआई की बैठक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: डीसीटीआई की पहली बैठक मंगलवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुई। वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वस्त्र उद्योग के व्यवस्थित विकास और सरकार को नीतिगत सुझाव देने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सरकार, उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों और वस्त्र क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में वस्त्र और परिधान क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए समन्वित रणनीति पर जोर दिया गया। परिषद ने रेशा, धागा, वस्त्र, प्रसंस्करण और परिधान क्षेत्रों में क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और मूल्य श्रृंखला की कमियों को दूर करने पर भी विचार हुआ। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने, नई पीढ़ी के रेशों और तकनीकी वस्त्रों में नवाचार बढ़ाने तथा अनुसंधान परिणामों को जल्द व्यावसायिक उपयोग में लाने पर जोर दिया गया।

जीएसटी परिषद की बैठक 8 को, गिरफ्तारी के अधिकार में बदलाव की तैयारी

ब्रिक्स सम्मेलन के कारण दूसरी बार टली बैठक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक अब 7 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को होगी। परिषद सचिवालय के अनुसार, कुछ जरूरी कारणों से बैठक की तारीख आगे बढ़ाई गई है। यह लगातार दूसरी बार है जब बैठक का कार्यक्रम बदला गया है। पहले बैठक 12 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के कारण इसे टालकर 7 अक्टूबर किया गया था।

बैठक में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधारों पर विचार किया जा सकता है। प्रस्तावित बदलावों में जीएसटी अधिकारियों की सीधे गिरफ्तारी करने की शक्ति वापस लेने और कर संबंधी आपराधिक मामलों की सीमा बढ़ाने की तैयारी शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 69 में संशोधन किया जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था में आयुक्त स्तर की मंजूरी के बाद जीएसटी अधिकारी गिरफ्तारी कर सकते हैं। बदलाव होने पर गिरफ्तारी के लिए न्यायालय की मंजूरी अनिवार्य होगी।

कर चोरी या फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों में आपराधिक कार्रवाई की सीमा भी एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके तहत पांच करोड़ रुपये से कम के मामलों में आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। वर्गीकरण, मूल्यांकन या इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े सामान्य विवादों को भी आपराधिक कार्रवाई के दायरे से बाहर रखने की तैयारी है। ऐसे मामलों में कारोबारियों और कर अधिकारियों के बीच लेन-देन की व्याख्या को लेकर मतभेद होने पर उसे आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा।

जीएसटी लागू होने के बाद फर्जी बिल और कर चोरी रोकने के लिए गिरफ्तारी की शक्ति दी गई थी। अब स्वचालित और आंकड़ा आधारित चालान मिलान व्यवस्था मजबूत होने के बाद इसमें बदलाव का प्रस्ताव है। गिरफ्तारी की शक्ति हटने के बावजूद कर वसूली, ब्याज और जुर्माना लगाने की नागरिक शक्तियां बरकरार रहेंगी।

स्पेशल खबर अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत रही जीडीपी वृद्धि, घरेलू मांग और निर्यात ने संभाली अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक का भरोसा बढ़ा, विकास दर का अनुमान 7.1 प्रतिशत

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले अप्रैल में जारी अनुमान में विकास दर 6.6 प्रतिशत रहने की बात कही गई थी। मंगलवार को जारी 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' में विश्व बैंक ने यह संशोधित अनुमान दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक व्यापार में चुनौतियों और दुनिया में जारी तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही।

विश्व बैंक के मुताबिक, भारत की आर्थिक वृद्धि में निवेश और घरेलू खपत की अहम भूमिका रही। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मांग बढ़ी। अच्छी कृषि, किसानों को सरकारी सहायता और सब्सिडी से ग्रामीण मांग को समर्थन मिला। वहीं, कर राहत और जीएसटी में

कटौती के बाद शहरी खपत में भी तेजी देखने को मिली। वैश्विक परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद भारत के निर्यात ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। इसे वित्त वर्ष 2026-27 की आर्थिक वृद्धि के लिए प्रमुख सकारात्मक कारकों में माना गया है।

आपूर्ति पक्ष पर औद्योगिक क्षेत्र ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। पहली तिमाही में बुनियादी ढांचे और निर्माण सामग्री से जुड़े क्षेत्र की वृद्धि 7.2 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष यह 6.1 प्रतिशत थी। भीषण गर्मी के कारण उपयोगिता सेवाओं की मांग बढ़ने से बिजली क्षेत्र में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विश्व बैंक के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025 में 7.2 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। नीतिगत उपायों और आसान ऋण माहौल ने वैश्विक व्यापार तनाव के प्रभाव को कम करने में मदद की। वित्त वर्ष 2026-27 की आगामी तिमाहियों में वृद्धि दर कुछ कम हो सकती है, लेकिन समग्र आर्थिक रुझान मजबूत रहने की उम्मीद है।

नई कार खरीदने की तैयारी है तो थोड़ा रुकें

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए अक्टूबर का महीना महत्वपूर्ण हो सकता है। इस महीने वाहन बाजार में कई नए मॉडल पेश किए जाने की तैयारी है। टोयोटा से लेकर होंडा, हुंडई, स्कोडा और रेनो जैसी कंपनियां अपने नए या अपडेटेड मॉडल बाजार में उतार सकती हैं। कार कंपनियां त्योहारी मांग को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल पेश करने पर जोर दे रही हैं। इस दौरान अलग-अलग श्रेणियों में ग्राहकों को नए विकल्प मिलने की उम्मीद है। इनमें कॉम्पैक्ट कार, एसयूवी और अन्य यात्री वाहन शामिल हैं। टोयोटा की ओर से ग्लांजा को लेकर बाजार में गतिविधि देखने को मिल सकती है। वहीं, होंडा की एलिवेट भी नए विकल्पों में शामिल है। एसयूवी श्रेणी में ग्राहकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए कंपनियां इस सेगमेंट पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हुंडई और स्कोडा भी नए मॉडल या अपडेटेड वाहनों के साथ बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की तैयारी में हैं। स्कोडा की स्लाविया और रेनो की डस्टर से जुड़े नए विकल्प भी कार खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

भारत के इस्पात क्षेत्र में लगातार वृद्धि, पहली छमाही में कच्चे इस्पात का उत्पादन 2.9 प्रतिशत बढ़ा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में भारत के इस्पात क्षेत्र में वृद्धि का क्रम जारी रहा। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन 85.1 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 82.7 मिलियन टन से 2.9 प्रतिशत अधिक है। तैयार इस्पात का उत्पादन भी 3.7 प्रतिशत बढ़कर 81.8 मिलियन टन पहुंच गया। गर्म धातु का उत्पादन 2.5 प्रतिशत बढ़कर 48.3 मिलियन टन रहा। सितंबर में कच्चे इस्पात का उत्पादन 14.1 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष के 13.7 मिलियन टन से 3.4 प्रतिशत अधिक है। तैयार इस्पात का उत्पादन 13.5 मिलियन टन रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 13.2 मिलियन टन था। इस अवधि में तैयार इस्पात की खपत 84.9 मिलियन टन रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 79 मिलियन टन से 7.5 प्रतिशत अधिक है। सितंबर में खपत 14.4 मिलियन टन रही, जो सालाना आधार पर 8 प्रतिशत की वृद्धि है। इस्पात की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। 26 सितंबर को 10 मिलीमीटर टीएमटी की कीमत 65,298 रुपये प्रति टन रही, जो जुलाई के मुकाबले 12.6 प्रतिशत अधिक है। एचआर कॉइल की कीमत 76,085 रुपये और सीआर कॉइल की कीमत 84,972 रुपये प्रति टन रही। अप्रैल-सितंबर के दौरान तैयार इस्पात का आयात 4.14 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष से 23.8 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में निर्यात 3.55 मिलियन टन रहा और भारत मात्रा के आधार पर तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक रहा।